The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 1 | January 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

भारत में औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा : सतत विकास की ओर एक रणनीतिक दृष्टिकोण

बलकरण कुमार
शोधार्थी स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
balkarankumar2023@gmail.com

डॉ0 राजीव कुमार रंजन
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
मुरारका कॉलेज सुलतानगंज
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
dr.rajivkumarranjanbgp@gmail.com

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:
विनिर्माण विस्तार, व्यापार प्रतिस्पर्धा, हरित ऊर्जा, एफडीआई, डिजिटल नवाचार

ABSTRACT

भारत की आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां उत्पादन क्षमता बढ़ाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं। यह शोध भारतीय सरकार के लिए प्रमुख सिफारिशों का विश्लेषण करता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार, व्यापार प्रतिस्पर्धा, विनियामक सुधार और हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर दिया गया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना ने विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को मजबूत करने और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में सुधार करने से भारत की निर्यात क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्योग-अकादमिक सहयोग से नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) के लिए वित्तीय और डिजिटल समर्थन से वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा

में सक्षम बनेंगे। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से भारत वैश्विक विनिर्माण और व्यापार परिदृश्य में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.14849394

1. परिचय :आत्मनिर्भरता से वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो विनिर्माण, ऊर्जा, और निर्यात क्षेत्रों में अपनी मजबूती स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास, नवाचार, और सतत विकास की रणनीतियों को अपनाकर भारत न केवल आत्मनिर्भर बनना चाहता है, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी अग्रणी स्थान प्राप्त करना चाहता है। हाल के वर्षों में, सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं, हरित ऊर्जा नीतियों, और वैश्विक व्यापार सहयोग को प्राथमिकता दी है, जिससे भारत का औद्योगिक और ऊर्जा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इस परिवर्तन को समझने के लिए हमें भारत के उद्योग, ऊर्जा और व्यापारिक नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार और आत्मनिर्भरता : भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी योजनाएं लागू की हैं। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए PLI योजनाओं को लागू किया गया है। सेमीकंडक्टर और बैटरी निर्माण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बनाए जा रहे हैं ताकि भारत वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत कर सके।

ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास की दिशा में बढ़ते कदम : भारत का ऊर्जा क्षेत्र भी एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा और आर्थिक सशक्तिकरण : निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) लागू किए जा रहे हैं, जिससे भारतीय वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों को अधिक अवसर मिलें। लॉजिस्टिक्स और परिवहन अवसंरचना में सुधार कर निर्यात लागत को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, एफडीआई नीतियों को सरल बनाया जा रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक गंतव्य बन सके।

भारत के औद्योगिक और ऊर्जा परिवर्तन की यह यात्रा न केवल देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगी।

भारत में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नवीनतम तकनीकों और नवाचार-आधारित उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए, उन्नत सामग्री (Advanced Materials) जैसे नैनोटेक्नोलॉजी, स्मार्ट मैटेरियल्स, और कंपोजिट्स का उपयोग विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है (Ninduwezuor-Ehiobu et al., 2023)। ये तकनीकें उत्पादों की गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देती हैं। आधुनिक निर्माण विधियों, डिजिटल

एकीकरण, और टिकाऊ औद्योगिक रणनीतियों को अपनाकर, भारत वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को और अधिक मजबूत कर सकता है। इससे न केवल घरेलू उद्योगों को लाभ मिलेगा, बल्कि निर्यात क्षमताओं में भी वृद्धि होगी, जिससे भारत एक आत्मनिर्भर और नवाचार-प्रधान औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकेगा।

साहित्य समीक्षा

Huo, J., Khan, I., Alharthi, M., Zafar, M. W., & Saeed, A. (2023). इस साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि सतत ऊर्जा नीतियाँ, सामाजिक-आर्थिक विकास, और पारिस्थितिक पदचिह्न एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। शोध में यह पाया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग और जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणीय प्रभावों को बढ़ाते हैं, जबकि सतत विकास नीतियाँ इन प्रभावों को कम करने में सहायक होती हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा मिलता है। अध्ययन इंगित करता है कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ हरित तकनीक और टिकाऊ ऊर्जा नीतियों को प्राथमिकता देने से दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सकता है। समग्र रूप से, यह निष्कर्ष नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए सतत विकास के दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जिससे सामाजिक-आर्थिक समृद्धि और पारिस्थितिक स्थिरता प्राप्त की जा सके।

Ninduwezuor-Ehiobu, N., et. all (2023). इस साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक विनिर्माण (Modern Manufacturing) में नवीन सामग्रियों (Innovative Materials) का एकीकरण अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता (Global Competitiveness) को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अध्ययन दर्शाता है कि नैनोटेक्नोलॉजी, कंपोजिट्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मैटेरियल्स और बायोमिमिक्री जैसी उन्नत सामग्रियाँ उत्पादों की कार्यक्षमता, दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार करने में सहायक होती हैं।

शोध के अनुसार, अमेरिका की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए सामग्री नवाचारों को बढ़ावा देना आवश्यक है। न केवल यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में सहायक होगा, बल्कि उद्योगों के तकनीकी विकास और आर्थिक मजबूती को भी बढ़ावा देगा। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत को सहयोगी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिससे नवाचार अनुकूल नीतियाँ बनाई जा सकें।

Chatenet, M., et al. (2022). साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक विकास भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि *मेक इन इंडिया* और *उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं* घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक रही हैं। ऊर्जा संक्रमण और स्थिरता पर किए गए शोध इंगित करते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर भारत हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा पर हुए अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करने से भारत की निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और डिजिटल नवाचार को औद्योगिक विकास के प्रमुख कारक माना गया है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का एकीकरण और विनियामक सुधार औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। ये निष्कर्ष

भारत के औद्योगिक परिवर्तन की व्यापक समझ प्रदान करते हैं, जो नीति-संचालित सुधारों और तकनीकी एकीकरण के महत्व को दर्शाते हैं, जिससे भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बना रह सकता है।

Saniuk, S., Grabowska, S., & Straka, M. (2022). इस साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्रांति 4.0 से 5.0 में परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय भूमिका को पुनः स्थापित करने और सतत विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को दर्शाता है। जहाँ *Industry 4.0* तकनीकी नवाचार और स्वचालन (Automation) पर केंद्रित थी, वहीं *Industry 5.0* मनुष्य-केंद्रित डिजिटलीकरण, स्थायित्व, और लचीलेपन (Resilience) को बढ़ावा देती है। शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक डिजिटलीकरण के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को स्वीकार करते हुए, सतत नीति निर्माण आवश्यक है।

औद्योगिक डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), और साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (CPS) के बढ़ते उपयोग से समाज में नई नौकरियों का सृजन और रोजगार संरचना में परिवर्तन देखा जा रहा है। हालांकि, यह भी आवश्यक है कि डिजिटल परिवर्तन केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक भलाई और पर्यावरण संतुलन को भी ध्यान में रखे। अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि Industry 5.0 को अपनाने से आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास को मजबूती मिलेगी।

Saniuk, S., Grabowska, S., & Straka, M. (2022). इस साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान और विकास (R&D) भारतीय दवा उद्योग की वित्तीय प्रदर्शन क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। अध्ययन में पाया गया कि नवाचार और व्यापारिक स्थिरता के बीच एक गहरा संबंध है, जिससे भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। *TRIPS* समझौते के बाद, भारतीय दवा उद्योग ने वैश्विक स्तर पर सस्ती दवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह "विश्व की फार्मेसी" के रूप में उभर कर आया है।

वित्तीय दृष्टिकोण से, *R&D* निवेश और लाभप्रदता के बीच एक द्विपक्षीय संबंध देखा गया है, जो भारतीय कंपनियों को दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा में बनाए रखता है। इसके अलावा, निर्यात बाजार में विस्तार, सरकारी नीतियों का समर्थन, और तकनीकी नवाचार भारतीय फार्मा उद्योग की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निरंतर अनुसंधान निवेश और नीति समर्थन से भारत की दवा कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से आगे बढ़ सकती हैं।

Olczyk, M., Kuc-Czarnecka, M., & Saltelli, A. (2022). इस साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि *ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (GCI) 4.0* की नई पद्धति प्रतिस्पर्धात्मकता की अधिक सटीक माप प्रदान करने का प्रयास करती है। पूर्ववर्ती GCI 2017 की तुलना में, नई पद्धति ने प्रतिस्पर्धात्मकता निर्धारण के स्तंभों की संख्या को कम कर दिया है, जिससे सूचकांक की प्रभावशीलता में सुधार हुआ है। अध्ययन इंगित करता है कि नवीनतम पद्धति में *उत्पाद बाजार* और *श्रम बाजार* जैसे केवल दो स्तंभ प्रमुख रूप से प्रभावी पाए गए हैं, जबकि पहले चार स्तंभों को समान महत्व दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, शोध से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि *वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF)* द्वारा निर्दिष्ट भारांक वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मकता को पूर्णतः परिलक्षित नहीं करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि 103 में से 35

परिवर्तनीय कारक (मुख्य रूप से राय-आधारित संकेतक) सूचकांक की गणना में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते, और इन्हें हटाने के बावजूद प्रतिस्पर्धात्मकता स्कोर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

अध्ययन के उद्देश्य

यह अध्ययन भारत के औद्योगिक और ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया को समझने और मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य विनिर्माण, ऊर्जा, और वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का विश्लेषण करना और आत्मनिर्भरता से लेकर वैश्विक नेतृत्व तक की संभावनाओं को उजागर करना है। यह अध्ययन विभिन्न नीतियों, सरकारी योजनाओं, और औद्योगिक क्षेत्रों की प्रगति का आकलन करता है ताकि भारत की आर्थिक वृद्धि और सतत विकास में सुधार लाने के लिए सटीक सिफारिशें दी जा सकें। साथ ही, यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियों की भूमिका को समझने और उनके प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

मुख्य उद्देश्य:

- औद्योगिक विकास का मूल्यांकन – भारत के विनिर्माण क्षेत्र में हो रहे विस्तार और आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए कदमों का अध्ययन करना।
- ऊर्जा संक्रमण की समीक्षा – भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और सतत विकास की दिशा में किए गए प्रयासों का विश्लेषण करना।
- वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा – भारत के निर्यात नीतियों, मुक्त व्यापार समझौतों (FTA), और लॉजिस्टिक्स सुधारों का अध्ययन करना।
- सरकारी नीतियों का प्रभाव – विभिन्न सरकारी योजनाओं, एफडीआई नीतियों, और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

शोध पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन द्वितीयक डेटा (Secondary Data) पर आधारित है, जिसे विभिन्न आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र किया गया है। प्रमुख स्रोतों में भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण (Indian Economic Survey), विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO), अक्टूबर 2024, डब्ल्यूटीओ व्यापार समीक्षा रिपोर्ट, दिसंबर 2024, तथा माही रिपोर्ट, Q3 2024: विश्व निर्माण उत्पादन (UNIDO) शामिल हैं। इसके अलावा, पीएमआई विनिर्माण (HSBC) एवं बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स से भी महत्वपूर्ण आँकड़े संकलित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स, और अन्य औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों और दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है। शोध में सरकारी नीतियों, उद्योग जगत के रुझानों, और ऊर्जा संक्रमण के पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। विभिन्न शोध पत्रों, वर्किंग पेपर्स, और अकादमिक लेखों को संदर्भित किया गया है ताकि उद्योग, ऊर्जा, और व्यापार क्षेत्र में भारत की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन किया जा सके। इस अध्ययन की कार्यप्रणाली में तुलनात्मक विश्लेषण, रुझान मूल्यांकन (Trend Analysis) और नीतिगत समीक्षा (Policy Review) को प्राथमिकता दी गई है, जिससे शोध के निष्कर्ष अधिक सटीक और तथ्यपरक बन सकें।

डेटा विश्लेषण के साथ परिणाम एवं चर्चा

2. भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएँ

भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 से 2030 के बीच भारत की जीडीपी में लगातार वृद्धि होगी, जो इसे 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा देगी। यह वृद्धि न केवल भारत के आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रुपये की विनिमय दर में भी परिवर्तन देखा जाएगा। आईएमएफ के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में 82.8 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक यह 85.6 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है। यह संकेत करता है कि भारत की आर्थिक नीतियाँ और व्यापारिक गतिविधियाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाए रखने में सफल होंगी।

वित्त वर्ष 2025 से 2030 तक भारत की जीडीपी और विनिमय दर का अनुमान (आईएमएफ)

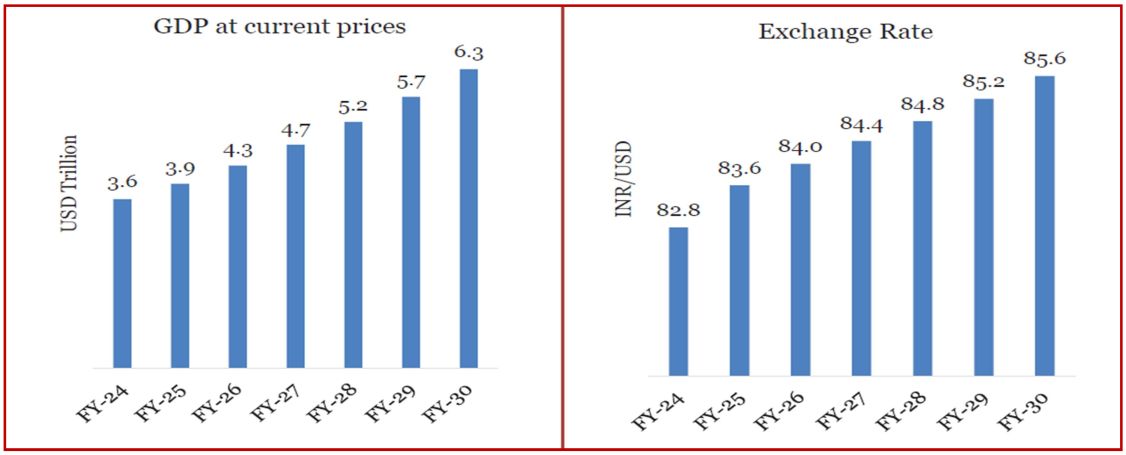

स्रोत: डब्ल्यूईओ, अक्टूबर, 2024

यह ग्राफ भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) और विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) का वित्त वर्ष 2025 से 2030 तक का अनुमान प्रस्तुत करता है। बाईं ओर दिखाया गया ग्राफ जीडीपी को मौजूदा मूल्यों पर प्रदर्शित करता है, जिसमें 2024 में 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इससे संकेत मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था आगामी वर्षों में मजबूत विकास दर बनाए रखेगी, जिससे आर्थिक वृद्धि और समग्र वित्तीय स्थिरता को बल मिलेगा।

दाईं ओर दिया गया ग्राफ विनिमय दर (INR/USD) को दर्शाता है, जिसमें भारतीय रुपया 2024 में 82.8 प्रति डॉलर से कमजोर होकर 2030 तक 85.6 प्रति डॉलर होने का अनुमान है। यह इंगित करता है कि भारतीय मुद्रा में मामूली गिरावट आ सकती है, जो वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और घरेलू वित्तीय नीतियों पर निर्भर

करेगी। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था विस्तार की ओर बढ़ रही है, लेकिन विनिमय दर में उतार–चढ़ाव बना रहेगा।

भारत की आर्थिक वृद्धि दर और विनिमय दर को देखते हुए, आगामी वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सतत विकास की ओर अग्रसर होगी। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, भारत की नाममात्र जीडीपी में निरंतर वृद्धि होगी, जिससे निवेश और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि, विनिमय दर में मामूली उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है, लेकिन इसकी वृद्धि दर अपेक्षाकृत धीमी रहने की संभावना है। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय रुपये में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे आयात-निर्यात संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इस संदर्भ में, भारत की मजबूत विकास संभावनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को और सशक्त बनाएंगी।

3. वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता और भारत

वर्तमान वैश्विक व्यापार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धात्मकता एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है, जो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता को प्रभावित करता है। भारत, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, अपने व्यापारिक नीतियों में सुधार कर वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों और संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्तियों के बावजूद, भारत का निर्यात क्षेत्र लचीला बना हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक अवसरों का विस्तार, नवाचार और डिजिटल व्यापार के उपयोग से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने से भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रभावी भागीदार बनने में सहायता मिलेगी।

नए आयात–प्रतिबंधात्मक उपायों का व्यापार कवरेज) बिलियन अमेरिकी डॉलर, असंचयी (

यह ग्राफ वैश्विक व्यापार में नए आयात-प्रतिबंधात्मक उपायों के प्रभाव को दर्शाता है, जो विभिन्न वर्षों में व्यापार कवरेज को अमेरिकी डॉलर में मापता है। 2013-2014 में व्यापार कवरेज में तीव्र वृद्धि देखी गई, जो 1183 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, लेकिन अगले वर्ष यह गिरकर 170 बिलियन डॉलर तक आ गई। इसके बाद, कुछ वर्षों तक यह अपेक्षाकृत स्थिर रहा, लेकिन 2019-2020 से इसमें लगातार वृद्धि देखी गई। 2023-2024 में व्यापार प्रतिबंधों का कवरेज 1320 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो संकेत देता है कि वैश्विक व्यापार पर नए प्रतिबंधों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।

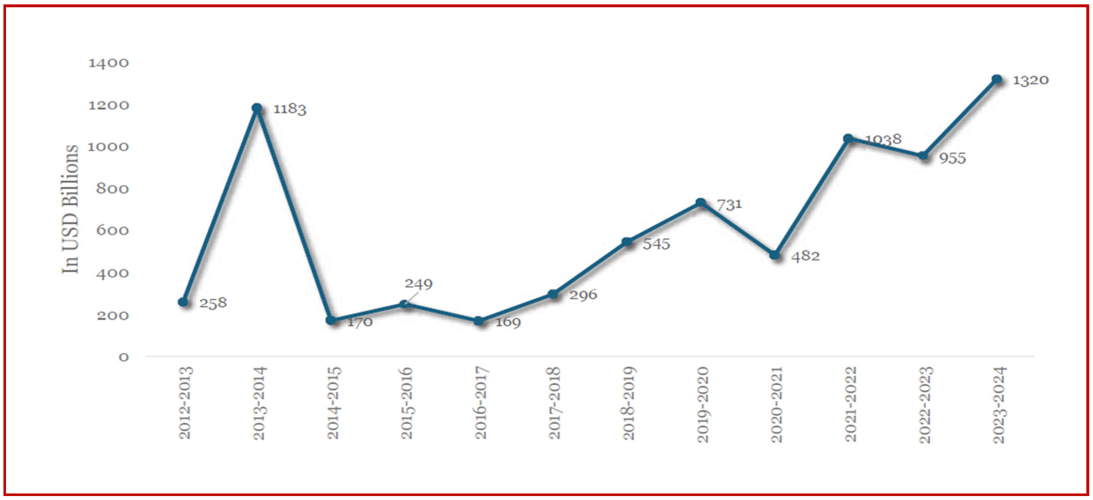

(**स्रोत:** व्यापार नीति समीक्षा निकाय को प्रस्तुत डब्ल्यूटीओ व्यापार समीक्षा रिपोर्ट; दिसंबर 2024)

इस संदर्भ में, दूसरा पाठ वैश्विक एफडीआई प्रवाह पर व्यापार प्रतिबंधों के प्रभाव को दर्शाता है। व्यापार बाधाओं के कारण, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अधिक संवेदनशील हो गई हैं। उच्च लागत और सख्त व्यापार नीतियों के कारण, एफडीआई प्रवाह सीमित हो सकता है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, व्यापार विखंडन से वैश्विक उत्पादन लागत में 0.2% से लेकर 7% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। यह विश्लेषण बताता है कि जैसे-जैसे व्यापार प्रतिबंध बढ़ेंगे, वैश्विक पूंजी अधिक स्थिर और सुरक्षित अर्थव्यवस्थाओं की तलाश करेगी, जिससे उभरते बाजारों की विकास संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

4. वैश्विक निर्माण क्षेत्र में भारत की भूमिका और संभावनाएँ

भारत के लिए वैश्विक निर्माण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के अनेक अवसर मौजूद हैं। उच्च आय वाले देशों ने पिछले दशक में अपने निर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग वैश्विक स्तर पर साझा किया है, जिससे चीन को सबसे अधिक लाभ हुआ है। भारत, जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, अपने औद्योगिक विकास में लगातार सुधार कर रहा है। निर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी के संदर्भ में भारत की वर्तमान स्थिति तुलनात्मक रूप से छोटी है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने की व्यापक संभावनाएँ हैं।

हालांकि, वैश्विक निर्माण क्षेत्र में उन्नति के लिए भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपूर्ति श्रृंखला की अस्थिरता, राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा लागत में वृद्धि और लॉजिस्टिक समस्याएँ शामिल हैं। इन बाधाओं के बावजूद, यदि भारत अपने कौशल विकास, तकनीकी नवाचार और नीति सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह निर्माण क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शैक्षिक संस्थानों को एकीकृत प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

निर्माण क्षेत्र में चयनित देशों का प्रदर्शन

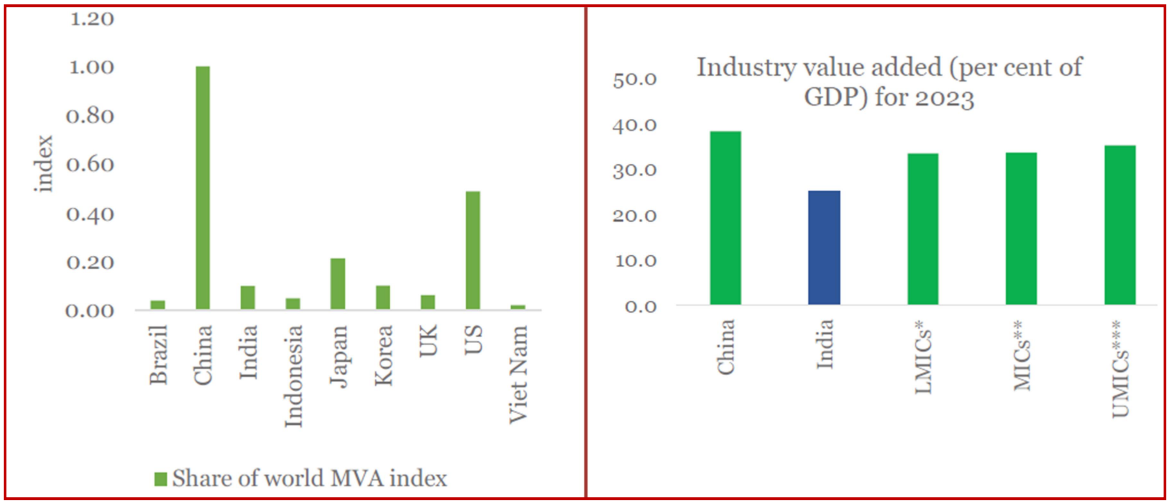

नोट: UNIDO का विश्व निर्माण मूल्य वर्धित (डाटा) सूचकांक वैश्विक निर्माण उत्पादन में किसी देश के निर्माण क्षेत्र के सापेक्ष योगदान को मापता है।

यह चार्ट विभिन्न देशों के निर्माण क्षेत्र में उनके योगदान और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उद्योग के मूल्य वर्धन को दर्शाता है। पहले ग्राफ में "शेयर ऑफ वर्ल्ड MVA इंडेक्स" के तहत यह दिखाया गया है कि चीन का योगदान वैश्विक निर्माण मूल्य वर्धित सूचकांक (MVA) में सबसे अधिक है, जबकि भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया का योगदान अपेक्षाकृत कम है।

दूसरे ग्राफ में, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उद्योग क्षेत्र के योगदान का प्रतिशत दिखाया गया है। इसमें चीन का औद्योगिक क्षेत्र GDP का बड़ा हिस्सा बनाता है, जबकि भारत का योगदान अपेक्षाकृत कम है। यह संकेत करता है कि भारत को अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वह वैश्विक निर्माण क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सके। UNIDO की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अपनी नीतियों और निवेश को इस दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता होगी ताकि वह निर्माण क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति को बेहतर बना सके।

5. औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि और चुनौतियाँ

वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि देखी गई, जिसमें प्रमुख योगदान खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्रों का रहा। हालाँकि, महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2021 में औद्योगिक क्षेत्र में संकुचन देखा गया था, जिसके बाद विकास में अस्थिरता बनी रही। चार्ट VII.2 (a&b) से यह स्पष्ट होता है कि वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक वृद्धि पिछले पाँच वर्षों के औसत से अधिक रही, विशेष रूप से निर्माण और बिजली क्षेत्रों में मजबूती देखी गई। हालाँकि, दूसरी तिमाही में औद्योगिक विकास दर 3.6% तक सीमित रह गई, जिसका मुख्य कारण प्रमुख व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं, मानसून के अप्रत्याशित प्रभाव और निर्माण क्षेत्र में सुस्ती रहा। इन

कारकों के बावजूद, भारत में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने और स्थिरता लाने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

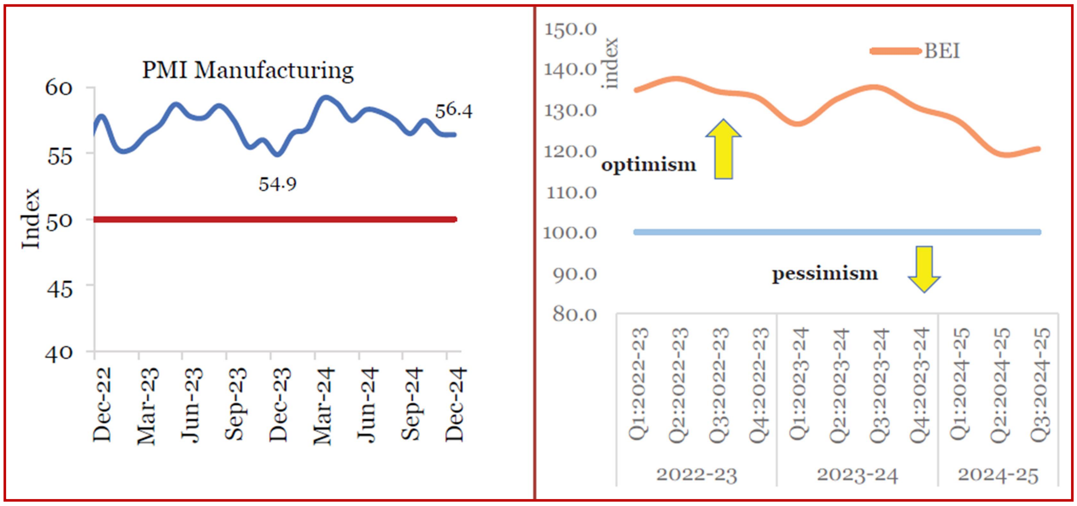

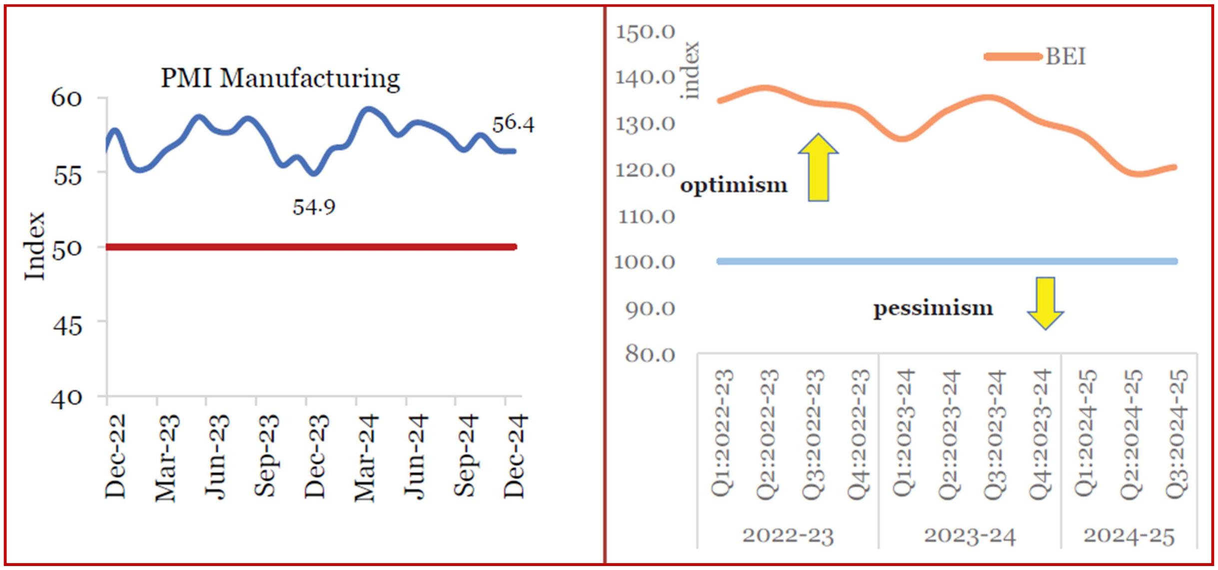

स्रोत : पीएमआई विनिर्माण (एचएसबीसी) & बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स

यह चार्ट दो महत्वपूर्ण संकेतकों को दर्शाता है: पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग (Purchasing Managers' Index - PMI) और बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स (BEI)। पहले चार्ट में पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को दिखाया गया है, जो विनिर्माण क्षेत्र में गतिविधि और व्यावसायिक स्थिति का संकेत देता है। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों में पीएमआई स्थिर स्तर से ऊपर बना हुआ है, जो 50 से अधिक होने का अर्थ यह है कि विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। हालांकि, मार्च 2024 में यह 54.9 तक गिरा, लेकिन बाद में यह 56.4 तक वापस बढ़ा, जिससे संकेत मिलता है कि उद्योग क्षेत्र में सुधार की प्रवृत्ति बनी हुई है।

दूसरा चार्ट बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स (BEI) को दर्शाता है, जिसमें उद्योग क्षेत्र में आशावाद (optimism) और निराशावाद (pessimism) को समझाया गया है। 2022-23 की पहली तिमाही में बीईआई 140 से अधिक था, लेकिन

बाद में इसमें गिरावट आई, जिससे यह संकेत मिलता है कि उद्योगों में विश्वास का स्तर कम हुआ। 2023-24 की चौथी तिमाही में एक गिरावट देखी गई, जो वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापारिक बाधाओं के कारण हो सकती है। हालांकि, 2024-25 की पहली तिमाही में एक हल्की वृद्धि देखी गई, जिससे उद्योगों में संभावनाओं की वापसी का संकेत मिलता है।

6. पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों का प्रदर्शन

ऑटोमोबाइल उद्योग :

भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वित्त वर्ष 2024 में इस उद्योग ने लगभग 12.5% की ग्रोथ दर्ज की और यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बढ़ती मांग, सरकार की पीएलआई (Production Linked Incentive) योजना, और हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर झुकाव इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2023-24 में दोपहिया (2W) वाहनों की बिक्री में 15% वृद्धि देखी गई, जबकि व्यावसायिक वाहनों (CV) में 8% की वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, EV सेगमेंट में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। EV निर्माण के लिए आवश्यक खनिज संसाधनों की आपूर्ति में चीन की प्रतिस्पर्धा अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बैटरी निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है, जिससे EV उत्पादन की लागत में कमी आएगी और घरेलू बाजार में इसकी पहुंच बढ़ेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग :

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हाल के वर्षों में काफी विकसित हुआ है, विशेष रूप से मोबाइल फोन निर्माण क्षेत्र में। वर्ष 2023-24 में भारत ने 58.4 बिलियन डॉलर मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात किया, जो वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'पीएलआई' योजनाओं ने इस क्षेत्र को गति दी है, जिससे मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भारत तेजी से निवेश आकर्षित कर रहा है। नए चिप निर्माण संयंत्रों की स्थापना से घरेलू उत्पादन को बल मिलेगा, जिससे देश को आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।

कपड़ा उद्योग :

भारत का कपड़ा उद्योग अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से निर्यात क्षेत्र में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यात में 6.2% की वृद्धि हुई। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और भारत की कपड़ा गुणवत्ता में सुधार के कारण यह उद्योग आगे बढ़ रहा है। सरकार की 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) योजना ने विशेष रूप से तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) और जैविक वस्त्रों (Organic Textiles) के उत्पादन को बढ़ावा दिया है।

हालांकि, इस क्षेत्र को अभी भी चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने हाल ही में यूरोप और अमेरिका के बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिससे अगले कुछ वर्षों में इस उद्योग की वृद्धि और मजबूत होने की संभावना है।

फार्मास्यूटिकल्स उद्योग :

भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। 2023-24 में भारतीय दवा उद्योग का कुल राजस्व 58.44 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वैक्सीन उत्पादन और जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत दुनिया का अग्रणी आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

सरकार द्वारा मेडिकल रिसर्च और नई दवा खोज में निवेश को बढ़ावा देने के कारण यह उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा, फार्मा क्षेत्र में हुई नवीनतम तकनीकी प्रगति और वैश्विक मांग में वृद्धि से भारत का फार्मा उद्योग 2025 तक 65 बिलियन डॉलर के स्तर को छू सकता है। इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

ऊपर दिए गए चार प्रमुख उद्योग—ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, और फार्मास्यूटिकल्स—भारत की आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक हैं। सरकार की नीतियों, विदेशी निवेश, और तकनीकी नवाचारों की मदद से ये उद्योग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा।

7. सरकार के लिए सिफारिशें

भारत की आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि को बनाए रखने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार को रणनीतिक कदम उठाने होंगे। आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने, निर्यात को प्रोत्साहित करने, और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार आवश्यक हैं। नीचे कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, जिन पर ध्यान देकर भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है।

विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और आत्मनिर्भरता

भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई (Production Linked Incentive) योजना का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले। सेमीकंडक्टर और बैटरी निर्माण को मजबूत करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बनाए जाने चाहिए, जिससे भारत वैश्विक चिप और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा, सप्लाई चेन को मजबूत करने और कच्चे माल की निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करना आवश्यक है।

वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में मजबूती

भारत को वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में मजबूती लाने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को तेजी से लागू करना चाहिए, ताकि वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा उद्योगों को अधिक निर्यात अवसर मिलें। निर्यात-उन्मुख उद्योगों को कर लाभ और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्यात संवर्धन नीति को और मजबूत करने की

आवश्यकता है। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर निर्यात लागत को कम किया जाना चाहिए, जिससे भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सके।

विनियामक सुधार और निवेश आकर्षण

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिए सरकार को निवेश नीतियों को और सरल बनाना चाहिए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना चाहिए। कर प्रणाली को सरलीकृत किया जाए ताकि नए उद्यमों और स्टार्टअप्स को औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करने में आसानी हो। इसके अलावा, बौद्धिक संपदा संरक्षण (Intellectual Property Rights - IPR) को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित किया जा सके और भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद मिल सके।

ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा (Green Energy) पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सरकार को सौर और पवन ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग हो सके। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने के लिए अनुकूल नीतियां बनाई जानी चाहिए, जिससे 2030 तक EV का उपयोग 50% तक बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही, औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सख्त पर्यावरणीय नियम लागू किए जाने चाहिए।

कौशल विकास और शिक्षा सुधार

आधुनिक उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को उन्नत करना होगा, जिससे युवा पीढ़ी को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा सके। अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में नवीन तकनीकों को अपनाया जा सके। इसके अलावा, इंडस्ट्री-एकेडेमिया पार्टनरशिप को मजबूत किया जाए, जिससे उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन प्राप्त हो सके और नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके।

औद्योगिक क्लस्टर और एसएमई (SME) समर्थन

भारत के *छोटे और मध्यम उद्यमों (SME)* को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्लस्टर्स विकसित किए जाएं, जिससे विनिर्माण और निर्यात केंद्रों को बढ़ावा मिले और उद्योगों की उत्पादकता में सुधार हो। *डिजिटल और ई-कॉमर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर* को सशक्त किया जाए ताकि छोटे उद्यम डिजिटल माध्यम से वैश्विक बाजारों तक अपनी पहुँच बना सकें और अपनी व्यावसायिक संभावनाओं का विस्तार कर सकें।

यदि भारत सरकार इन सिफारिशों पर कार्य करती है, तो न केवल औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश की आर्थिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी वैश्विक स्तर पर सशक्त होगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल व्यापार, और तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और भारत एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर सकेगा।

8. निष्कर्ष

भारत की आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि को गति देने के लिए विनिर्माण, निर्यात, निवेश और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देना आवश्यक है। वर्तमान में, भारत का विनिर्माण क्षेत्र GDP का लगभग 17% योगदान देता है, लेकिन इसे 2025 तक 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जिसके लिए पीएलआई (Production Linked Incentive) योजना को और विस्तार देना जरूरी है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को अपने बैटरी निर्माण और चिप उत्पादन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए FTA (Free Trade Agreements) को तेजी से लागू करना होगा, ताकि भारतीय वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों को निर्यात अवसरों में वृद्धि मिले। वर्तमान में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात $24 बिलियन तक पहुंच चुका है, लेकिन उचित नीतियों से इसे और ऊंचाई दी जा सकती है। इसके अलावा, ईवी नीति को और अनुकूल बनाकर 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा जा सकता है।

सरकार को FDI (Foreign Direct Investment) नीतियों को सरल बनाकर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाना होगा, जिससे 2023 में 84 अरब डॉलर के विदेशी निवेश को और अधिक आकर्षित किया जा सके। साथ ही, बौद्धिक संपदा संरक्षण (IPR) को मजबूत करना आवश्यक है, जिससे नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर भारत की निर्यात लागत को कम करना आवश्यक है, ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके।

भारत को ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने की आवश्यकता है। सौर और पवन ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देकर 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सख्त पर्यावरणीय नियम लागू किए जाने चाहिए, ताकि भारत नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य 2070 तक प्राप्त कर सके।

कौशल विकास और शिक्षा सुधारों को बढ़ावा देकर, उद्योगों को प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराना जरूरी है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में निवेश कर, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को नई तकनीकों से लैस किया जा सकता है। इसी तरह, SME (Small and Medium Enterprises) को वित्तीय सहायता प्रदान कर डिजिटल और ई-कॉमर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जाए, ताकि छोटे उद्यम वैश्विक बाजार तक अपनी पहुँच बना सकें।

यदि भारत सरकार इन नीतिगत सुधारों पर कार्य करती है, तो भारत एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम बढ़ा सकता है। ये रणनीतियाँ न केवल आर्थिक वृद्धि को गति देंगी, बल्कि भारत को नवाचार, निर्यात और सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाएंगी।

संदर्भ सूची

1. Huo, J., Khan, I., Alharthi, M., Zafar, M. W., & Saeed, A. (2023). *Sustainable energy policy, socio-economic development, and ecological footprint: The economic significance of natural*

resources, population growth, and industrial development. Utilities Policy, 81, 101490. https://doi.org/10.1016/j.jup.2023.101490

2. Ninduwezuor-Ehiobu, N., Tula, O. A., Daraojimba, C., Ofonagoro, K. A., Ogunjobi, O. A., Gidiagba, J. O., Egbokhaebho, B. A., & Banso, A. A. (2023). *Exploring Innovative Material Integration in Modern Manufacturing for Advancing U.S. Competitiveness in Sustainable Global Economy. Engineering Science & Technology Journal, 4(3).* https://doi.org/10.51594/estj.v4i3.558

3. Chatenet, M., Pollet, B. G., Dekel, D. R., Dionigi, F., Deseure, J., Millet, P., Braatz, R. D., Bazant, M. Z., Eikerling, M., Staffell, I., Balcombe, P., Shao-Horn, Y., & Schäfer, H. (2022). *Water electrolysis: From textbook knowledge to the latest scientific strategies and industrial developments. Chemical Society Reviews, 51*(4583-4762). https://doi.org/10.1039/D0CS01079K

4. Saniuk, S., Grabowska, S., & Straka, M. (2022). *Identification of Social and Economic Expectations: Contextual Reasons for the Transformation Process of Industry 4.0 into the Industry 5.0 Concept. Sustainability, 14(3)*, 1391. https://doi.org/10.3390/su14031391

5. Nandy, M. (2022). *Global Competitiveness of Pharmaceutical Industry of India: Trends and Strategies.* In *Relationship between R&D and Financial Performance in Indian Pharmaceutical Industry.* Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6921-7_5

6. Olczyk, M., Kuc-Czarnecka, M., & Saltelli, A. (2022). *Changes in the Global Competitiveness Index 4.0 Methodology: The Improved Approach of Competitiveness Benchmarking. Journal of Competitiveness, 14*, 118-135. https://doi.org/10.7441/joc.2022.01.07

7. amitkapoor. (2023, October 18). Competitiveness and India Growth Story – Institute for Competitiveness. Retrieved February 2, 2025, from Competitiveness.in website: https://www.competitiveness.in/competitiveness-and-india-growth-story/

8. CII Team. (2023, July 4). Revitalizing India's Competitiveness: A Blueprint for Global Excellence - CII Blog. Retrieved February 2, 2025, from CII Blog website: https://ciiblog.in/revitalizing-indias-competitiveness-a-blueprint-for-global-excellence/

9. Enhancing The Competitive Spirit of India. (2025). Retrieved February 2, 2025, from Drishti IAS website: https://www.drishtiias.com/daily-news-editorials/enhancing-the-competitive-spirit-of-india

10. IBEF. (2022). Manufacturing Sector in India: Market Size, FDI, Govt Initiatives | IBEF. Retrieved from www.ibef.org website: https://www.ibef.org/industry/manufacturing-sector-india

11. India's Advancing Role in Global Trade Competitiveness. (2024). Retrieved from Pib.gov.in website: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2079986

12. ISID | Institute for Studies in Industrial Development. (2022, August 25). Retrieved February 2, 2025, from ISID website: https://isid.org.in/research-programme/sectoral-studies-on-competitiveness-of-indian-manufacturing/

13. Ministry of Commerce & Industry. (2017). Retrieved from Pib.gov.in website: https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153203&ModuleId=3&reg=3&lang=1

14. Narayana IAS Academy Official. (2024, June 26). Will India Improve Its Export Competitiveness? | Narayana IAS Academy. Retrieved February 2, 2025, from YouTube website: https://www.youtube.com/watch?v=X_yl1FMupzc